***Date*:** 18-05-2020
***Publication*:** Hindustan Hindi
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया के पास सौ साल का कोयला

- कोल इंडिया टू ग्रो स्ट्रांगर के साथ मंत्री का ट्वीट
- वर्तमान में 173 बिलियन टन कोयले का भंडार

धनबाद | विशेष संवाददाता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग की घोषणा के एक दिन बाद रविवार को कोयला मंत्री प्रसाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र निर्माण में कोल इंडिया की अहम भूमिका है। कोल इंडिया को सरकार मजबूत कर रही है। 2023-24 में कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता एक बिलियन टन की होगी।

कोल इंडिया के पास वर्तमान में 173 बिलियन टन कोयले का भंडार है। यानी अगले सौ साल तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है। कोल इंडिया को अभी हाल में 16 नए कोल ब्लॉक भी दिए गए हैं। मालूम हो केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग की मंजूरी कोल सेक्टर में दी है। इसके बाद कोयला मंत्री का यह ट्वीट कोयला मंत्रालय के ट्वीटर हैंडल पर ट्रेंड कर रहा है। यानी संकेत दिया गया है कि कॉमर्शियल माइनिंग से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बताते चलें कि कॉमर्शियल माइनिंग से कोल सेक्टर में उदारीकरण का दौर शुरू होगा। खनन एवं कोयले के वितरण (बिक्री) में प्राइवेट इंवेस्टमेंट (निजी निवेश) का मार्ग प्रशस्त होगा।

निजी कंपनियों को कोयला खनन के साथ-साथ बेचने का अधिकार दिया गया है। इससे कोल इंडिया के कोयले की कीमत और आपूर्ति पर नियंत्रण संबंधी एकाधिकार खत्म हो जाएगा। सरकार का मानना है कि कोयला आयात कम करने में कॉमर्शियल माइनिंग से मदद मिलेगी। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। मालूम हो कि भारत दुनिया का अब दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश होने के बाद सालाना 200 मिलियन टन से अधिक कोयले का आयात करता है।

कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध शुरू

धनबाद । ट्रेड यूनियनों की अलग-अलग हुई बैठक में कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद किया गया। सभी यूनियनों उक्त मुद्दे पर केंद्र सरकार की निंदा की एवं आरोप लगाया कि सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने पर आमद है। सुधार के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर मजदूरों के हक को छीनने का काम कर रही है।

22 मई को हल्ला बोल-हमला बोल : सीटू

जगजीवन नगर धनबाद में बीसीकेयू, बीएसएसआर यूनियन तथा बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में घोषणा की गई कि कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ 22 मई को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विरोध करेंगे। केंद्र के जनविरोधी एजेंडे जो कॉरपोरेट घराने व विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। उसे सफल नहीं होने देंगे। कोरोना के नाम पर विदेशी व मल्टीनेशनल कंपनियों को लुभाने के लिए मालिक पक्षीय श्रम कानूनों में बदलाव आत्मनिर्भरता को चोट तो पहुंचती ही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा कर सबको भ्रम में फंसा दिया है। असीम हलदर, भारत भूषण, हेमंत मिश्रा सहित कई यूनियन नेता मौके पर मौजूद थे।

कोल इंडिया में एक हफ्ते की हड़ताल हो : आरसीएमएस

आरसीएमएस की बैठक में सभी श्रमिक संगठनों से एकजुट हो कोल इंडिया में सप्ताह भर के लिए हड़ताल कर कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध करने का आह्वान किया गया। कहा गया कि केंद्र सरकार कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में कोयला क्षेत्र को बेचने का निर्णय ले चुकी है। यह एकतरफा फैसला है, जो कोल इंडिया के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के खिलाफ है। माइनिंग के सारे नियम कानून को ताख पर रखकर कोयला खदानों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। रोजगार के नाम पर ठेका मजदूरों की फौज खड़ी कर शोषण करने की योजना सरकार की है। बैठक में मन्नान मल्लिक, ओपी लाल, ब्रजेंद्र सिंह, एके झा, रामप्रीत यादव आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे : बीएमएस

आत्मनिर्भर भारत बनाने एवं कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर भारत सरकार काम के घंटे बढ़ाने, प्रोविडेंट फंड अंशदान कम करने, कोयला उद्योग का निजीकरण करने के साथ साथ कमर्शियल माइनिंग की स्वीकृति देने जैसा निर्णय लेकर स्थाई एवं अस्थाई मजदूरों पर प्रहार कर रही है। भारतीय मजदूर संघ ऐसे निर्णय का पुरजोर विरोध के साथ साथ भर्त्सना भी करता है। जेबीसीसीआई सदस्य सह अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के बीके राय ने कहा कि 18 मई को जिलाअध्यक्ष के माध्यम से एवं 20 मई को उद्योग के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज सरकार की नीति का विरोध करेंगे।

मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन : एटक

एटक ने भी आंदोलन की घोषणा की है। बताया कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन की दिल्ली बैठक में 22 को आंदोलन की घोषणा हुई। श्रम कानूनों के साथ साथ अब कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। केंद्र सरकार शुरू से निजीकरण के पक्ष में रही है। मौजूदा परिस्थिति का सरकार लाभ उठाते हुए अपने एजेंडे को लागू कर रही है। एटक नेता लखन लाल महतो ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की मामले पर जल्दी बैठक होगी।

कॉमर्शियल माइनिंग का फैसला गलत: चटर्जी

केंद्र सरकार द्वारा पहली बार कॉमर्शियल माइनिंग को मंजूरी देने का पूर्व विधायक केएस चटर्जी ने विरोध किया है। बिहार प्रदेश कोलियरी मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष चटर्जी ने कहा कि सरकार का यह फैसला कोयला उद्योग के लिए काला दिन जैसा है। इससे श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा व उन्हें आर्थिक नुकसान भी होगा। कांग्रेस ने कभी कोल इंडिया के निजीकरण के बारे में नहीं सोचा, लेकिन भाजपा ने यह गलत निर्णय ले लिया।

***Date*:** 18-05-2020
***Publication*:** The Asian Age
***Edition*:** New Delhi

CIL begins work to develop ₹2,474-cr CBM projects

State-owned CIL has initiated the process of development of coal bed methane projects with an estimated investment of Rs 2,474 crore, and has invited domestic as well as global firms for exploration of the blocks in West Bengal and Jharkhand. The PSU will develop both projects on revenue sharing basis. Coal India Ltd arm Bharat Coking Coal Limited (BCCL) offered Jharia CBM Block-I for exploration and marketing of CBM.

***Date*:** 19-05-2020
***Publication*:** The Telegraph
***Edition*:** Kolkata

Status quo for CIL

NEW DELHI: The government does not intend to privatise state-owned Coal India Ltd, Union minister Pralhad Joshi said on Monday. The statement comes in the wake of the government opening up coal mining for the private sector and stating that commercial mining will be done on revenue sharing mechanism instead of fixed rupee/tonne. PTI

***Date*:**19-05-2020
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Kolkata

कोल इंडिया के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश : कोयला मंत्री

- वर्ष 2023-24 तक एक बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य होगा आसान

आसनसोल. केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोल इंडिया लिमिटेड में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का फैसला लिया गया है. इस फैसले से कोल इंडिया को वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने एक बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने की राह आसान होगी. कोल इंडिया के लिये यह एक बड़ा अवसर है. कंपनी नयी खदाने खोलते हुये अधिक से अधिक कोयला उत्पादन कर देश में हो रहे कोयले के आयात की भरपाई कर सकती है. उन्होंने विश्वास जताया कि आनेवाले समय में कोल इंडिया अपने उत्पादन से सालाना एक सौ मिलियन टन कोयले के आयात की भरपाई करेगी. श्री जोशी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार का कोल इंडिया के निजीकरण का इरादा नहीं है, बल्कि सरकार कोल इंडिया को मजबूत कर रही है और इसे आगे भी और मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त कोयला भंडार है, जो देश में एक सौ वर्षों से अधिक तक बिजली बनाने के लिये पर्याप्त है. हाल ही में सरकार ने कोल इंडिया को 16 नये कोयला ब्लॉक भी दिये हैं. कोल इंडिया परिवार को आश्वस्त करते हुये श्री जोशी ने कहा कि सरकार को कोल इंडिया पर गर्व है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जायेगा.

***Date*:** 19-05-2020
***Publication*:** Deshpran
***Edition*:** Ranchi

कोल इंडिया के पास 173 बिलियन टन कोल भंडार: जोशी

रांची : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग की घोषणा के एक दिन बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र निर्माण में कोल इंडिया की अहम भूमिका है। कोल इंडिया को सरकार मजबूत कर रही है। 2023-24 में कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता एक बिलियन टन की होगी। कोल इंडिया के पास वर्तमान में 173 बिलियन टन कोयले का भंडार है। यानी अगले सौ साल तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है। कोल इंडिया को अभी हाल में 16 नए कोल ब्लॉक भी दिए गए हैं। मालूम हो केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग की मंजूरी कोल सेक्टर में दी है। इसके बाद कोयला मंत्री का यह ट्वीट कोयला मंत्रालय के ट्वीटर हैंडल पर ट्रेंड कर रहा है। यानी संकेत दिया गया है कि कॉमर्शियल माइनिंग से चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

***Date*:** 20-05-2020
***Publication*:** Free Press Journal
***Edition*:** Mumbai

Coal India not to be privatised, says Union Minister Pralhad Joshi

Union Minister of Coal and Mines Pralhad Joshi on May 18, 2020 said that the Govt. has announced an investment of Rs. 50,000 crore under "Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan" to create and develop infrastructure facilities for Coal India. It will help CIL achieve 1 billion tonnes coal production target by FY 2023-24. It's also an opportunity for CIL to open up new mines and increase coal production to reduce country's coal imports saving valuable forex. He expected that CIL will substitute 100 million tonnes of coal import annually in near future. Joshi reiterated that the Government of India does not intend to privatize Coal India Ltd. Instead, the government is strengthening CIL and will continue to do so. He further added that CIL has a coal reserve which will last for over 100 years. Recently, the government has allotted 16 new coal blocks to CIL to help it fuel the Indian economy. He reassured the Coal India family that the Government is proud of CIL and it will only strengthen it in the days to come.
Photo WCL

***Date*:** 21-05-2020
***Publication*:** The Financial Express
***Edition*:** Kolkata

Revenue share model for coal auction gets nod

FE BUREAU
New Delhi, May 20

INDICATING ITS READINESS to forego a large part of its revenue from coal mining if it results in a jump in the country's coal production, the government on Wednesday approved a new market-determined revenue share model for auctioning off coal assets, ending the fixed fee/tonne regime that turned off private investors, even as the sector has gradually been opened up to them in recent years.

However, a coal miner in India still has to pay assorted taxes to the central, state and local governments — including royalties, a hefty ₹400/tonne GST compensation cess and contribution to district mineral funds — which work out to more than 50% of the base price of the fuel, much higher than in other coal-rich countries like Australia (7%), South Africa (11%) and the US (4%), analysts said.

With coal imports surging and becoming a drag on the country's current account

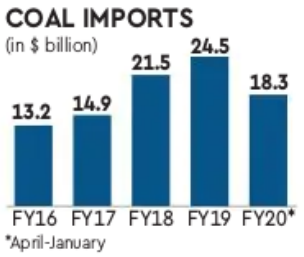

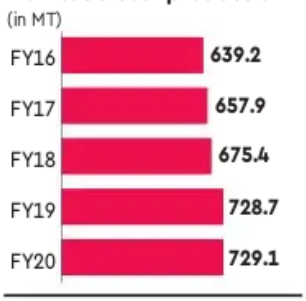

(imports were $24.5 billion in FY19 and $18.3 billion in April-January, financial year 2019-20), the government has over the last more than two years taken a series of steps to populate the sector with more investors and technology players.

Continued on Page 2

Revenue share model for coal auction gets nod

IT ALLOWED commercial coal mining by the private sector and removed the end-use curbs for captive coal mines, virtually removing the captive/non-captive distinction. Also, 100% FDI is now allowed in the sector via the automatic route.

The Cabinet on Wednesday approved a new auction methodology for coal blocks as per which the floor price benchmarked for the auctions would be 4% of the revenue share, incrementing in multiples of 0.5%. If bidders raise the government's revenue share to more than 10% in the auctions, bids would be accepted in multiples of 0.25% of the revenue share thereafter.

Sources said that the requirement of prior experience for prospective bidders for coal blocks has also been removed from the list of eligibility criteria for the bidders. Also, the price of coal for commercial mining are said to be determined on the basis of a 'National Coal Index', which would include a weighted combination of monthly prices of coal in various channels of transaction. The national coal index will update the prices every two months. The upfront amount payable by the highest bidder would be 0.25% of value of geological reserve of the mines, capped at ₹100 crore for mines with up to 200 million tonne reserves and ₹500 crore with blocks with higher coal reserves.

Analysts say the new methodology might be attractive for domestic user industries which are likely to bid for coal assets more aggressively now with the removal of end-use restrictions that will allow them to sell surplus after meeting own requirements in the open market. However, while the idea may also be to bring global mining giants such as BHP Billiton, Rio Tinto and Glencore into India's coal mining sector, these firms are seemingly withdrawing from the sector in a gradual manner and as a result don't seem to have a keen interest in India's coal sector at this juncture.

"The methodology is oriented to make maximum coal available in the market at the earliest and it also enables adequate competition which will allow discovery of market prices for the blocks and faster development of coal blocks. Higher investment will create direct and indirect employment in coal bearing areas especially in the mining sector and will have an impact on economic development of these regions," the government said in a statement.

***Date*:** 22-05-2020
***Publication*:** The Hitavada
***Edition*:** Nagpur

Women 'coal warriors' of WCL challenging COVID-19

■ Staff Reporter

Women in WCL are performing various duties.

AMID lockdown imposed in the wake of COVID-19 outbreak, women staffers of Western Coalfields Limited (WCL) are discharging their duties diligently. According to WCL, the women workforce has explored the power of social media to bring a wave of positivity amongst peer group.

Wearing helmet, face-mask and gloves, Pooja Samarth is in command of a Heavy Earth Moving Machinery (HEMM) Hydraulic Shovel at Umrer Opencast Coal Project of WCL. She is a Shovel Operator working for eight hours in a shift, extracting overburden to expose coal required for power generation. She is taking care of her parents and also reaches to the needy along with fellow workers distributing food packets during current grim situation.

Nidhu Rani, Armature Winder at Pathakhera Regional Workshop of WCL in adjoining State of Madhya Pradesh, works taking all precautions. She is ensuring repairs and maintenance of machines deployed for mining operation. She takes care of her family and is an active member of Shakti Group educating fellow workmen and their family members to take precaution against COVID-19.

Aashima Dalal, Staff Nurse, takes extra effort to arrive early at the office to ensure everyone wears mask and uses sanitiser at the entrance before heading for work. Other women employees working in mines are spreading awareness and motivating people to be cautious at workplace. Bhagya Shree, a young Category-I employee of Kanhan Area, is among the staffers who ensure that collieries and machines are well-sanitised before the shift starts every day.

"With changing time, the society is gradually acknowledging women like us who work in field. But, what makes it easier above all is the feeling of empowerment that we get here," says Purva Naidu, who has worked as Head of Human Resources in a Mine Unit and is now working in WCL Headquarters, stated a press release. Shakti Group is a voluntary group of women employees of WCL in each Area and Headquarters. It works to support and strengthen their co-workers at workplace and home too. Through visits to colony and home, and now with food distribution, Shakti Group has been on the frontline.

WCL's woman workforce comprises non-executives and executives. Non-executives are trained for both mining and non-mining operations. A substantial number of these trained women employees are working as Shovel Operator, Electrician, Armature Winder, Welder, Moulder, Pump Operator, Valveman etc in Opencast Mines or in Workshops. Others are engaged in offices as Clerk, Data Entry Operator, Accountant, Console Operator, Chemist etc. Some are working as Staff Nurse, Paramedics and Security Guards.

***Date*:** 23-05-2020
***Publication*:** Business Standard Hindi
***Edition*:** New Delhi

पर्यावरण मंत्रालय ने कोयले की अनिवार्य धुलाई का नियम हटाया

श्रेया जय
नई दिल्ली, 22 मई

पांच साल पहले भारत सरकार ने अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के तहत कोयले की धुलाई को अनिवार्य किया था जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है। गुरुवार को जारी एक गजट अधिसूचना में मंत्रालय ने ताप बिजली उत्पादन स्टेशनों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की अनिवार्य धुलाई को समाप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर दिया।

गजट अधिसूचना में कहा गया है, 'ताप बिजली संयंत्रों के लिए राख की मात्रा या दूरी की शर्तों के बिना कोयले के इस्तेमाल की अनुमति होगी।' बिजनेस स्टैंडर्ड ने गजट अधिसूचना का अवलोकन किया है।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के तहत 2014 में कोयला खदानों से 500 किलोमीटर दूर स्थित सभी ताप बिजली इकाइयों को होने वाली कोयले की आपूर्ति से पहले उसकी धुलाई को अनिवार्य कर दिया था। भारत सरकार ने यह कदम जलवायु परिवर्तन की चर्चाओं में भारत के रुख को मद्देनजर रखते हुए उठाया था। इसमें भारत ने कहा था कि वह कोयला की खपत कटौती करने की बजाय उत्सर्जन नियंत्रण पर ध्यान देगा।

पर्यावरण मंत्रालय ने उसी वर्ष जारी अपने दिशानिर्देशों में कहा, '500–750 किलोमीटर, 750–1000 किलोमीटर के बीच स्थित बिजली स्टेशनों को ऐसे कोयले की आपूर्ति की जाएगी जिसमें राख की मात्रा तिमाही औसत पर 34 फीसदी से अधिक नहीं होगी। यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी।' इसलिए कोयला कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे धुले हुए/सम्मिश्रित या लाभकारी कोयले की आपूर्ति करें।

गजट अधिसूचना में कहा गया है कि कोयला मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण तीव्र विधायी कार्रवाई की आवश्यकता बताई थी।

अधिसूचना में कहा गया है, 'कोयला मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा अप्रत्याशित कोविड–19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप देश में बिजली उत्पादन के लिए कोयला क्षेत्र की मांग को बढ़ा कर घरेलू कोयले के इस्तेमाल की तुरंत आवश्यकता को देखते हुए, अधिसूचना को शीघ्र जारी करना वांछनीय है।'

कोयला मंत्रालय का मानना है कि औसत राख की मात्रा को 34 फीसदी पर बनाए रखने की जरूरत उद्योगों को कोयला आयात करने के लिए प्रेरित करता है जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है। मंत्रालय ने एक अलग नीति प्रस्ताव में ताप बिजली क्षेत्र को कोयले की जरूरत घरेलू स्रोतों से पूरी करने और कोयला आयात को शून्य करने के लिए कहा है।

***Date*:** 23-05-2020
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया ने पीएम राहत कोष में 61 करोड़ दिया

रांची. कोल इंडिया ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 61 करोड़ रुपये दिया है. कोविड-19 आने के बाद कोल इंडिया कर्मियों ने एक-एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है. एटक नेता लखन लाल महतो ने बताया कि जेसीसी की सहमति के बाद सभी कर्मियों ने राहत कोष में पैसा देने का निर्णय लिया था.

***Date*:** 23-05-2020
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Kolkata

कोकिंग कोल लिंकेज पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला

- नॉन रेगुलर सेक्टर को 30 वर्षों तक दिया जायेगा कोल लिंकेज

सांकतोड़िया. केंद्र सरकार ने कोकिंग कोल लिंकेज को लेकर एक एतिहासिक निर्णय लिया है. इसके तहत नॉन रेगुलर सेक्टर को अगले 30 वर्ष के लिए कोल लिंकेज देने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय हार्डकोक उद्योगों के लिए संजीवनी का काम करेगा. वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार ने इन उद्योगों को लिंकेज देना बंद कर दिया था. इससे तमाम हार्डकोक उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गए थे. सरकार से लगातार कोल लिंकेज देने की मांग की जा रही थी. हार्डकोक उद्योग नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता है. अब इन्हें कोल इंडिया व बीसीसीएल से एक निर्धारित दर पर प्रतिमाह कोयला मिलेगा. इन्हें ऑक्शन में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी. सरकार के इस निर्णय से लगभग 250 हार्डकोक उद्योगों को नया जीवन मिलेगा. इनमें फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत 83 हार्डकोक आते हैं. उद्यमियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है.

उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोल इंडिया व बीसीसीएल सरकार के निर्णय को अमलीजामा पहनाएगी. रेवेन्यू शेयर के आधार पर कोयला व लिग्नाइट खदानों की नीलामी करने का भी निर्णय लिया गया. कमर्शियल माइनिंग के लिए बोली लगानेवालों को कुछ फीसद राजस्व शेयर सरकार को देना होगा. फ्लोर प्राइस राजस्व हिस्सेदारी का चार फीसद होगा. बिडिंग रेवेन्यू शेयर के दस फीसद होने तक 0.5 फीसद के गुणक में स्वीकार किया जाएगा. इसके बाद यह .25 फीसद के गुणक में स्वीकार किया जाएगा. कोयले की बिक्री और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कमर्शियल कोल माइनिंग और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कोकिंग कोल लिंकेज 30 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है. मैं इन निर्णयों का स्वागत करता हूं. केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने (ट्वीटर पर) कहा कि 30 वर्ष के लिए लिंकेज बढ़ाने से इस उद्योग का पुनरुद्धार होगा. हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से स्थानीय कोयला उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. कोल कंपनियों ने सही से क्रियान्वयन किया तो हार्डकोक उद्योग की पुरानी रौनक लौट सकती है.

***Date*:** 25-05-2020
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Ranchi

कोल इंडिया में बड़े निवेश से होगा लाभ

वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया की सालाना उत्पादन क्षमता एक बिलियन टन करने का लक्ष्य है। जिस पर 50 हजार करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। बड़े पैमाने पर नियोजन के अवसर भी मिलेंगे। झारखंड देश का 39% कोल रिजर्व वाला राज्य है। आने वाले दिनों में झारखंड में कोल क्षेत्र का विस्तार बड़े पैमाने में संथाल परगना व चतरा जिला में होने जा रहा है। विदित हो कि टोकीसुद-1 कोल ब्लॉक भारत सरकार के कंपनियों को दिया जा चुका है।